

बिहार में यूरेनियम संसाधन संयंत्र की स्थापना

2560. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अणु ऊर्जा के विभिन्न स्रोत कौन से हैं तथा उनकी उपलब्धता का ब्यौरा क्या है और सिंहभूम सहित अन्य कौन से स्थान हैं जहां यह प्राप्त होती है तथा उसकी मात्रा और किस्म का ब्यौरा क्या है और सिंहभूम में कौन से ऐसे स्थान हैं जहां 600 टन निर्देशित और अनुमेय श्रेणियों की अणु ऊर्जा मिली है ; और

(ख) उस स्थान का नाम क्या है जहां यूरेनियम संसाधन संयंत्र लगाया जाना है और यह कब तक चालू कर दिया जाएगा और उस संयंत्र में कब तक उत्पादन आरंभ होगा ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) बिहार में सिंहभूम प्रणोद पट्टी के यूरेनियम-लौह (यूरेनीफेस) बहुल सुप्रसिद्ध क्षेत्र में यूरेनियम पाया जाता है। यह पट्टी 160 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। यूरेनियम का खनन सिंहभूम जिले के जादूगोडा नामक स्थान पर किया रहा है। बिहार के अन्य स्थानों में, जहां यूरेनियम पाया गया है, सिंहभूम जिले के तुरुमडीह, नरवा पहाड़, भोहलडीह-घाडकंध, भाटिन और पलामू जिले के बिदा-नागनहा शामिल हैं। देश में पाया जाने वाला अधिकांश यूरेनियम बिहार में है। परमाणु ऊर्जा का

विकास करने के लिए आवश्यक थोरियम बेरीलियन, नायोबियम, टैंग्स्टेलम आदि जैसे अन्य खनिज पदार्थ सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, नवाधा और रांची जिलों में पाये जाते हैं।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में जादूगोडा स्थित वर्तमान यूरेनियम मिल के विस्तार के लिए तथा साथ ही नरवापहाड़ और तुष्मडीह में नई खाने और मिलें स्थापित करने के लिए प्रावधान किया गया है।

सीमेंट के मूल्य में वृद्धि

2561. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सीमेंट के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कारण से मध्यम वर्ग के लोगों ने मकान बनवाने का विचार ही त्याग दिया है ;

(ग) क्या सरकार को और अधिक मकान निर्माण करने की योजनाएं सीमेंट की कमी से ठप्प हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) सीमेंट के रेल भाड़े में हुई वृद्धि के प्रावधान लिए लेवी सीमेंट के रेल भाड़ा मुक्त मूल्य में दिनांक 2.7.1983 से 52 रुपये प्रति मी० टन की वृद्धि की गई है। गैर-लेवी सीमेंट मूल्य नियंत्रण और वितरण नियंत्रण से मुक्त है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"Preservation and growth of the environment around the Himalayas"

2562. SHRI SURESH KALMADI:
SHRI KALRAJ MISHRA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Himalayas are facing an ecological disaster due to outdated forest policy with emphasis on commercial tree planting; and

(b) if so, what measures Government propose to take for the preservation and growth of environment around Himalayas?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT (SHRI DIGVIJAY SINH): (a) and (b) It is well known that the Himalayas are geologically young and very fragile. The ecological problems of this region are mainly on account of biotic pressures and loss of vegetal cover.

The measures already initiated or proposed to be undertaken for preservation of Himalayan environment include:

(i) Action-oriented eco-development research has been initiated in all the Himalayan Universities to find solutions to the local problem;

(ii) The Institute for Himalayan Environment and Development is being established to focus attention on special problem of the region.

(iii) Doon Valley has been taken up on a pilot project to come out with an environmentally compatible Development package for the Hilly areas.

(iv) A detailed project for the rehabilitation of Himalayan Foothills is being worked out with emphasis on soil and watershed management.

(v) Guidelines have been worked out for the trekking and expeditions covering such items as preservation of flora and fauna, disposal of camping sites.

(vi) Setting up of National Parks and Biosphere Reserves are proposed from Kashmir to the North East.

(vii) Strict environmental impact assessment of development projects such as industries, power, transport.

(viii) Reforestation and soil conservation, on priority.

(ix) Enactment of National Forest Conservation Act, 1980.

(x) Taking up integrated arrear development projects in the catchment of flood prone rivers.

Setting up of working group to study the economic and social conditions of Scheduled Castes

2563. SHRI PANDURANG DHARMAJI JADHAV: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether Government have set up a working group to study the economic and social conditions of the Scheduled Castes during the Seventh Plan period;

(b) if so, what is the composition and whether there is any Scheduled Caste member taken on the working group; and

(c) what are the details of priorities of work with which the group has been entrusted?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI S. B. CHAVAN): (a) to (c) Yes, Sir. The composition and terms of reference of the Working Group on Development of Scheduled Castes for the Seventh Five Year Plan are given in O.M. No. PC/BC/11-8(2)/83 dated